PC-VI/81
RBE NO. 38 /2009

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2008/PN1/13 **NEW DELHI, dated 18.02.2009.**

The GMs & FA&CAOs,
All Zonal Railways & Production Units,
(As per mailing list).

Subject : Implementation of Government's decision on the recommendations of the Sixth CPC - Revision of provisions regulating gratuity.

\+ + + + +

A copy of Department of Pension & Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M.No.7/7/2008-P&PW(F) dated 13th February, 2009 on the above subject is attached for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on the Railways also. DOP&PW's O.M. dated 2.9.2008 referred in the enclosed O.M. was adopted on the Railways vide this office letter of even number dated 15.9.2008.

2. Please acknowledge receipt.

Encl: One.

(SUNIL BHARDWAJ)
Deputy Director Finance (Estt.)III,
Railway Board.

No.7/7/2008-P&PW (F)
Government of India
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare
****

Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
dated 12th February, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of Government's decision on the recommendation of the Sixth CPC – Revision of provisions regulating gratuity -

The undersigned is directed to say that in terms of para 7.1 of this Department's O.M. No.38/37/2008-P&PW(A) dated the 2nd September, 2008 issued in implementation of the decision taken on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission, the benefit of adding years of qualifying service for the purpose of computation of pension shall stand withdrawn with effect from the date of issue of the O.M.

2. Sixth Central Pay Commission in Para 5.1.33 of its Report made the following recommendation:

> "Linkage of full pension with 33 years of qualifying service should be dispensed with. Once an employee renders the minimum pensionable service of 20 years, pension should be paid at 50% of the average emoluments received during the past 10 months or the pay last drawn, whichever is more beneficial to the retiring employee. Simultaneously, the extant benefit of adding years of qualifying service for purposes of computing pension/related benefits should be withdrawn as it would no longer be relevant."

This recommendation was accepted by Government of India vide Resolution No.38/37/2008-P&PW (A) dated 29th August, 2008.

3. It is clear from the above recommendations/decisions, that the benefit of adding years of qualifying service is withdrawn for the purpose of computing pension as well as other related benefits such as gratuity.

4. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure U.O. No.4.2/40/2009-IC dated 12.2.2009

5. Ministry of Agriculture etc. are requested to take into consideration the above position while computing pension and gratuity of government servants who have retired since 2.9.2008.

(M.P. Singh)
Director (PP)
Tele:24624802

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

सं. 7/7/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

* * *

लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.
दिनांक : 13 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन – उपदान को विनियमित करने वाले प्रावधानों में संशोधन के संबंध में –

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में जारी इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 2.9.2008 के पैरा सं. 7.1 की शर्तों के अनुसार पेंशन की परिकलन के उद्देश्यार्थ अर्हक सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से वापस हो जाएगा ।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.33 में निम्नलिखित सिफारिश की :

> "पूर्ण पेंशन की अर्हक सेवा के 33 वर्ष के साथ लिंकेज को बंद कर देना चाहिए । जैसे ही कोई कर्मचारी 20 वर्ष की न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा दे चुका होता है, तो पिछले 10 महीने में प्राप्त वेतन के औसत अथवा आहरित विगत वेतन, इनमें से जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए लाभप्रद हो, के 50 प्रतिशत पर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए । इसके साथ-साथ, पेंशन/संबंधित लाभ की गणना हेतु अर्हक सेवा के जोड़े गए वर्षों का वर्तमान लाभ वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अब सुसंगत नहीं होगा ।"

यह सिफारिश संकल्प सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 29 अगस्त, 2008 द्वारा सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई ।

3. उपयुक्त सिफारिशों/निर्णयों से स्पष्ट है कि पैंशन और अन्य संबंधित लाभ जैसे उपदान के परिकलन के उद्देश्यार्थ अर्हक सेवा को जोड़े गए वर्षों का लाभ वापस लिया जाता है।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के यू0 ओ0 सं0 4.2/40/2009-आई-सी, दिनांक 12 फरवरी, 2009 द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृषि मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि जो सरकारी कर्मचारी 2.9 2008 से सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी पैंशन और उपदान का परिकलन करते समय उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखें।

(एम0 पी0 सिंह)
निदेशक (पी0 पी0)
दूरभाष: 24624802

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रति:-

मानक सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उच्चतम न्यायालय, सी. एण्ड ए. जी., संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि।